ACHIEVERS IAS ACADEMY

SUMMARY OF THE HINDU

FOR BPSC EXAMINATION

HINDI

DATE

27/07/2023

+91 8434931877, +91 7250667974

www.achieversiaspatna.co.in

New Patliputra Colony, Road No. 4A, Near Tennis Court, Patna-13

THE HINDU 27.07-2023 National

मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में मंजूरभारत समूह चाहता है कि पीएम मोदी मणिपुर में लोकसभास्पीकरओएमबिड़लानेबुधवारकोअविश्वासप्रस्तावकोहरीझंडीदेदी.

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने प्रस्ताव पेश किया। विपक्षी सदस्यों से सलाह के बाद ही स्पीकर इसकी तारीख जारी करेंगे.

शीर्षक: एफएटीएफ का हवाला देते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से मिश्रा को ईडी प्रमुख बने रहने देने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वर्तमान ईडी प्रमुख एसके मिश्रा को 15 अक्टूबर तक पद पर बने रहने की अनुमति देने के लिए 27 जुलाई को सरकार के तत्काल आवेदन पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की, क्योंकि यह एफएटीएफ (वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स) के चल रहे मूल्यांकन के लिए आवश्यक था।

इससे पहले 11 जुलाई के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे कहा था.मिश्राको 31 जुलाईतकपदछोड़नाहोगा। केंद्र ने अपने आवेदन केंद्र में कहा, "ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर, एक ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी है जो देश भर में मनी लॉन्ड्रिंग जांच और कार्यवाही की समग्र स्थिति और प्रक्रियाओं, संचालन और गतिविधियों की जटिलताओं से अच्छी तरह परिचित हो।"जांचएजेंसी, ईडीकेमामलोंकेशीर्षपरहै," केंद्रकेआवेदनमेंआगेकहागया

केंद्र ने आग्रह किया, "इस स्तर पर ईडी में नेतृत्व में कोई भी परिवर्तन मूल्यांकन टीम को आवश्यक सहायता प्रदान करने की एजेंसी की क्षमता को काफी हद तक ख़राब कर देगा और इससे भारत के राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।"

एफएटीएफ आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में देशों को उनके प्रदर्शन के अनुसार सूचीबद्ध करने का काम करता है। यह आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग आदि जैसे खतरों से निपटने के लिए देशों को सहायता प्रदान करता है।

विधेयक में जन्म नियंत्रण डिजिटलीकरण का प्रस्ताव है

सरकारनेलोकसभामेंजन्मऔरमृत्युपंजीकरणसंशोधनविधेयक 2023 पेशकियाहै। विधेयक में राज्यों के लिए केंद्र के नागरिक पंजीकरण प्रणाली पोर्टल पर जन्म और मृत्यु को पंजीकृत करना और भारत के रजिस्ट्रार जनरल के साथ डेटा साझा करना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इससे केंद्रीय डेटाबेस को अद्यतन करने में मदद मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप कुशल और सेवाओं और सामाजिक लाभों की पारदर्शी डिलीवरी। इससे "जन्मतिथि और स्थान को साबित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता से बचा जा सकेगा"।

उत्पन्न डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र सर्वव्यापी दस्तावेज होगा जिसका उपयोग शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, नौकरी, पासपोर्ट या आधार, मतदाता नामांकन, विवाह के पंजीकरण और अन्य के लिए किया जा सकता है।

लोकसभा ने वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक पारित किया

बिलमेंकुछप्रमुखबिंदुइसप्रकारहैं:

1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार से कहा था कि वह उस भूमि के टुकड़े को संरक्षित करे जिसके नीचे पेड़ हैं, भले ही उसे वन घोषित न किया गया हो। ऐसी भूमि को घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार पर था। नया विधेयक किसी भी गैर वन भूमि को वन के रूप में संरक्षित घोषित करने की शक्ति देता है जिसे केवल केंद्र द्वारा घोषित किया जा सकता है।

बुनियादी ढांचे और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के निर्माण के लिए सरकार द्वारा 100 किमी की सीमा के अंतर्गत वनों का उपयोग सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

राज्य सरकार को किसी भी वन भूमि को निजी संस्था को आवंटित करने के लिए केंद्र की अनुमति की आवश्यकता होगी।
जंगल में चेक पोस्ट, बाड़ लगाने, पुल बनाने की अनुमति होगी।बिलवन भूमि में चिड़ियाघर, सफारीऔर इको पर्यटन सुविधाएं चलाने की भीअनुमति देता है।

केंद्र ने 2 कश्मीरी प्रवासियों को विधानसभा में नामांकित करने के लिए विधेयक पेश किया

केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम 2023 विधेयक पेश किया। विधेयक में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में "कश्मीरी विस्थापितों" के 2 सदस्यों को नामांकित करने का प्रावधान है। उनमें से एक महिला होगी.इसमेंपीओकेमेंरहनेवालोंकेलिएएकसीटआरक्षितकरनेकाभीप्रस्तावहै।

1989-90 के दौरान, जब जम्मू-कश्मीर में हिंसा चरम पर थी, लाखों कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी छोड़कर जम्मू, दिल्ली और देश के कई अन्य हिस्सों में बस गए थे।

- 1947 में पाकिस्तानी आक्रमण के मद्देनजर लगभग 31,779 परिवार पीओके से चले गए। 1965 और 1972 के दौरान लगभग 10, 065 परिवार भारत में प्रवेश कर गए

530 जिलों को मैला ढोने से मुक्त बताया गया: केंद्र

सामाजिक न्याय मंत्रालय ने राज्यसभा में मैला ढोने की प्रथा के बारे में अपने जवाब में निम्नलिखित बातें बताईं:
जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से हैं, जिन्होंने अब तक सबसे अधिक जिलों को मैला ढोने से मुक्त घोषित किया है।
पिछले पांच वर्षों में मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण किसी भी मौत की सूचना नहीं मिली है, हालांकि नालियों और स्केप्टिक टैंकों की सफाई करते समय 330 लोगों की मौत हो गई है।
जिन राज्यों को मैनुअल स्कैवेंजिंग से 100% मुक्त घोषित किया गया है वे हैं बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु।
सभी सीवर और सैपेटी टैंकों की सफाई को मशीनीकृत करने के लिए इस वर्ष नमस्ते योजना शुरू की गई है।
मैनुअल स्केवेंजिंग का अर्थ है मैन्युअल रूप से सफाई करना, शुष्क शौचालय, पागल शौचालयों और संशय टैंकों में मानव मल को संभालना।

एनडीए के तीसरे कार्यकाल में भारत शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा: प्रधानमंत्री

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पीएममोदीनेबुधवारकोराष्ट्रीयराजधानीमेंनवविकसितआईटीपीओकॉम्प्लेक्सकाउद्घाटनकिया। पुनर्विकसित परिसर को भारतमंडपमनामदियागयाहै। यह दिल्ली में आगामी G20 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, "हमारे पहले कार्यकाल में, भारत विश्व अर्थव्यवस्था रैंकिंग में 10वें स्थान पर था। दूसरे कार्यकाल में, यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, मैं कह रहा हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में यह दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। यह मोदी की गारंटी है।"

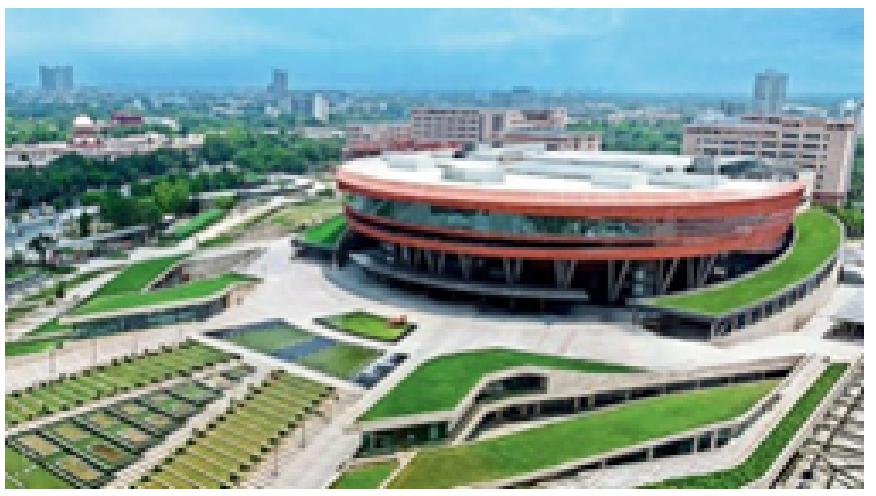

आईटीपीओ जी20 की मेजबानी करेगा

जम्मू-कश्मीर में विरोध के बीच, सरकार अनुसूचित सूची में और समूह जोड़ेगी

नेसेट द्वारा न्यायिक सुधार विधेयक केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए जो जम्मू-कश्मीर में शिक्षा और रोजगार के लिए आरक्षण संरचना को बदलने जा रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक -

- गड्डा ब्राह्मण, कोली और पद्दारो जनजातियों को जम्मू और कश्मीर जनजातीय सूची में जोड़ा जाएगा।

इस कदम का जम्मू-कश्मीर के कई जनजातीय समूहों, विशेषकर पीर पंजाल क्षेत्र में रहने वाले गुज्जर और बकरवालों द्वारा विरोध किया जा रहा है।

- जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023 - यह विधेयक जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी)" और "अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)" को फिर से परिभाषित करेगा। इससे राज्य 105वें संविधान संशोधन को अक्षरशः लागू करने में सक्षम होगा।

105वां संशोधन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपना एसईबीसी घोषित करने का अधिकार बताता है।

दुनिया

चीन ने पर्ज के संकेत में पूर्व मंत्री क़िन गैंग का अतीत साफ़ किया।

चीननेबुधवारकोविदेशमंत्रालयकीवेबसाइटसेहटाएगएविदेशमंत्रीकिनगैंगकीपिछलीजानकारी, वीडियोऔरभाषणहटादिए। ऐसा आम तौर पर देश का अपमान करने वाले या राजनीतिक घोटाले में शामिल किसी व्यक्ति के साथ किया जाता है

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने बीजिंग में अपनी दैनिक ब्रीफिंग में किन गैंग को हटाने का कोई भी कारण बताने से इनकार कर दिया।

उन्होंने बार-बार कहा कि उन्हें उनके निष्कासन के बारे में केवल सिन्हुआ समाचार चैनल द्वारा पोस्ट की गई जानकारी थी।

किनगैंग केबारे में:

किनगैन्फएकसमयराष्ट्रपतिशीजिनपिंगकेप्रोटोकॉलमंत्रीथे, उन्हेंराष्ट्रपतिशीजिनपिंगकाकरीबीमानाजाताथा। दिसंबर में उन्हें विदेश मंत्री के पद पर आसीन किया गया। हालाँकि वह पिछले 30 दिनों से सार्वजनिक मंच से अनुपस्थित थे, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि यह गलत है।

मंगलवार को चीन ने आधिकारिक तौर पर उन्हें हटाने की घोषणा की.हालाँकिवहराज्यपार्षदबनेहुएहैं। उनकी अनुपस्थिति में विदेश मंत्रालय उनके पूर्ववर्ती वांग यी संभाल रहे हैं।

कम्बोडियन प्रधानमंत्री हुन सेन 4 दशकों के बाद पद छोड़ेंगे।

कंबोडिया के सर्वोच्च सेवारत प्रधानमंत्रियों में से एक हुन सेन ने बुधवार को घोषणा की कि वह प्रधानमंत्री के पद से हट जाएंगे और यह पद अपने बेटे हुन खमेर को सौंप देंगे।

उनकी कॉम्बोडिया पीपुल्स पार्टी (सीपीपी) ने रविवार को हुए कुल मतदान में 82% वोट हासिल कर भारी जीत हासिल की। हालाँकि यूरोपीय संघ और अमेरिका ने चुनाव को न तो स्वतंत्र और न ही निष्पक्ष बताया है।

ब्लिंकन ने टोनहा का दौरा किया और चीन की कार्रवाई की आलोचना की।

अमेरिकीविदेशमंत्रीएंटनीब्लिंकननेबुधवारकोटोंगाकादौराकिया। उन्होंने वहां एक अमेरिकी दूतावास का उद्घाटन किया।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें चीन की शिकारी आर्थिक गतिविधियों, गैरकानूनी समुद्री दावों और सैन्यीकरण पर बढ़ते फोकस के बारे में चिंता है

चीन और अमेरिका दोनो प्रशांत छेत्र के छोटे देस पर अपना दोस्ती बढ़ने में लगे हैं

इजराइल की शीर्ष अदालत विवादास्पद न्यायिक बदलाव के पहले भाग के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

इज़राइलमेंनागरिकसमाजनेहालहीमेंपिछलेन्यायिकसुधारविधेयककोरद्दकरनेकेलिएइज़राइलकेसर्वोच्चन्यायालयमेंयाचिकादायरकीहै।अदालतनेइसेसितंबरमेंसुनवाईकेलिएसूचीबद्धकियाहै।

इस बीच इजराइल के प्रमुख शहरों में उस विवादास्पद विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है जो सरकारी कानूनों पर सवाल उठाने की अदालत की शक्ति को भंग कर देता है।

सम्पादकीय -1

सदन को एकजुट करना.

प्रधानमंत्री को मणिपुर के लोगों को आश्वस्त करने के लिए संसद को एक मंच के रूप में उपयोग करना चाहिए

संपादकीय के बारे में:

संपादकीय अविश्वास प्रस्ताव के बारे में है और प्रधानमंत्री को मणिपुर के लोगों को आश्वस्त करने के लिए इसका उपयोग कैसे करना चाहिए।

पीएममोदी केखिलाफअविश्वासप्रस्ताव;

बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओएन बिड़ला की मंजूरी के बाद अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया.प्रस्तावतभीस्वीकृतहोताहैजबउसपर 50 सदस्योंकेहस्ताक्षरहों। पीएम मोदी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और देंगे.भाषण। विपक्ष काफी समय से पीएम से मणिपुर पर बोलने की मांग कर रहा है, लेकिन पीएम नहीं बोले.उम्मीदकीजानीचाहिएकियहपीएममोदीकेलिएमणिपुरपरबोलनेऔरसरकारकेकदमकेबारेमेंवहांकेलोगोंकोआश्वस्त करनेकाएकअवसरहोगा।

मणिपुर के संबंध में:

मणिपुर को लेकर विपक्ष और सरकार दोनों एक मत नजर आ रहे हैं, सरकार भी इस पर चर्चा के लिए राजी हो गई । लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि पीएम को बोलना पड़ेगा.विपक्ष को ऐसी मांगें छोड़नी चाहिए और जो उसके पास है उसपर चर्चा करनी चाहिए।' किसी भी ऐसी मांग को लेकर संसद का आयोजन करना जो राहत देने वाली न लगे।

संपादकीय -2

लचीला, लेकिन न्यायसंगत

असंतुलित विकास, जो गरीब देशों को दरकिनार कर देता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का जोखिम उठाता है।

संपादकीय के बारे में:

संपादकीय इंटरनेशनल मू फोरम (आईएमएफ) के विश्व आर्थिक आउटलुक में नवीनतम अपडेट के बारे में बात करता है। इसने वैश्विक वृद्धि को 20 आधार अंकों तक उन्नत किया है। लेकिन कुछ गंभीर मुद्दे भी हैं जिन पर इसने बात की है।

विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में:

इसने 2023 में वैश्विक विकास दर को पिछले 2.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया है।

जो चिंताएँ दूर होती दिख रहीहैं:

ऐसा लगता है कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड में बैंक संकट सुलझ गया है, अमेरिकी ऋण सीमा गतिरोध भी सुलझ गया है, इससे कुछ राहत मिली है।

आगेकी चिंताएँ:

आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरी ओलिवर गिउरिंचस ने कहा कि अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली चिंताएं हैं:

वैश्विक और घरेलू प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है और अनिश्चितता बढ़ गई है।

महामारी के बाद चीन के खुलने से उसके निर्यात और मांग में भी मंदी देखी जा रही है।

रूस यूक्रेन युद्ध से यूरोजोन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। यूरो देश पहले रूसी गैस निर्यात पर निर्भर थे, अब भी इसके विकल्प पर कठिनाई महसूस कर रहे हैं

यूक्रेन से अनाज पास पर समझौते को रद्द करने के रूस के फैसले से कम आय वाले देशों में अनाज की कीमतें 15 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं।